WWJMRD 2018; 4(2): 436-440
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
UGC Approved Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

सुनिता
शोध छात्रा, भूगोल विभाग, ओ.पी. जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू राजस्थान, भारत

प्रियंका
शोध छात्रा, भू–विज्ञान विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई (राजस्थान), भारत

Correspondence:
सुनिता
शोध छात्रा, भूगोल विभाग, ओ.पी. जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू राजस्थान, भारत

सीकर शहर में नगरीकरण की प्रवृत्ति का अध्ययन, राजस्थान

सुनिता, प्रियंका

सारांश
नगरीय क्षेत्रों का भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि में अधिक वृद्धि 'नगरीकरण' कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। नगरीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व और मानवीय क्रियाकलाप उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। नगरीय क्षेत्र में आमतौर पर नगरों, कस्बों, या उपनगरीय विस्तारों को सम्मिलित किया जाता है लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता। नगरीय क्षेत्र के विस्तार का मापन जनसंख्या घनत्व और अव्यवस्थित फैलाव के विश्लेषण के लिए और नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के निर्धारण के लिए किया जाता है। शहरीकरण को भारत में 5000 व्यक्तियों की न्यूनतम आबादी को शहरीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 75 प्रतिशत पुरुष गैर–कृषि गतिविधियों में शामिल हैं और प्रति वर्ग किमी कम से कम 400 व्यक्तियों का घनत्व हो। इसके अलावा, एक नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत के साथ–साथ एक छावनी बोर्ड वाले सभी सांविधिक कस्बों को "अर्बन" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सीकर शहर में भी लगातार शिक्षा सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के कारण नगरीकरण में वृद्धि दर्ज की गई है। यहां नगरीकरण हेतु पर्यटन उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

Keywords: नगरीकरण, सीकर शहर, शिक्षा सुविधाएं, पर्यटन उद्योग, उपनगरीय, शहरीकरण, सांविधिक, वाणिज्यिक, आंकड़ा इंटरनेट, चतुर्भुजाकार।

परिचय
आधुनिक युग में नगरीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में प्रगट हुई है। यहाँ बढ़ते हुए नगरीकरण की प्रवृति आर्थिक विकास तथा औधोगिक विकास का सूचक है। औधोगिक विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना के साथ साथ व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं का भी विस्तार होता है एवं बाजार का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार साधनों के अभाव के कारण बड़ी मात्रा में लोग गाँव से शहरों की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं। भारत में नगरीकरण की गति बहुत अधिक नहीं रही। 1911 में कुल नगरीय जनसंख्या मात्र 11प्रतिशत थी, जो 1941 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 30 वर्ष में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि मात्र 3 प्रतिशत रही। 1951–9161 के बीच नगरीय जनसंख्या में मात्र 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 1961 में नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.81 प्रतिशत रही व 2011 में नगरीय जनसंख्या 31.16 प्रतिशत रही। यदि राजस्थान राज्य में नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करें तो 1951 में 18.50 प्रतिशत थी व 1971 में 17.63 प्रतिशत रही वही 1991 में 22.88 प्रतिशत रही 2001 में 23. 39 प्रतिशत रही। व 2011 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 24.89 प्रतिशत रही। सीकर जिले में नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करें तो 1921 में यहां नगरीय जनसंख्या 21080 थी जो 1951 में बढकर 44140, 1991 में 148272 हो गई। वहीं 2001 में यह 185925 व 2011 में बढकर 244497 तक पहुंच गई है। शहर के मास्टर प्लान से भी स्पष्ट है कि भविष्य में यहां ओर भी अधिक नगरीकरण की संभावनाएं मौजूद हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य
यहां प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. सीकर शहर में बढ़ते नगरीकरण की प्रवृत्ति की जानकारी प्रदान करना।
2. नगरीकरण से उत्पन्न सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की जानकारी प्रदान करना।
3- नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

आंकडा एकत्रीकरण एवं शोध प्रविधि

सामान्यतः शोध प्रविधि प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह होती है, यहाँ प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों में भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त आंकडों, राजस्थान नगर नियोजन विभाग, सीकर जिले के जिला राजपत्र, नगरपालिका पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, इंटरनेट, पुस्तकों आदि का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सीकर शहर में नगरीकरण की प्रवृत्ति को जानने के लिए 1991 और 2020 की भुवन विकास इमेजरी की सहायता लेते हुए मानचित्रीकरण विधि को अपनाया गया है। मानचित्रीकरण के लिए ।त्ब ळप् 10.2 सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

भारत के उत्तर–पश्चिम भाग मे ंस्थित राजस्थान प्रदेश विषम चतुर्भुजाकार आकृति में है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। सीकर जिला राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। तथा यह राजस्थान के थार मरुस्थल के 12 जिलों के अन्तर्•त आता है। सीकर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अन्तर्गत कुछ भाग मरुस्थलीय क्षेत्र, कुछ समतल मैदान तथा कुछ क्षेत्र अरावली के अन्तर्गत आता है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7732 वर्ग किमी है जो राज्य का 2.25 प्रतिशत है। इसका अक्षांशीय विस्तार 27̊ 21′ से 28̊ 12′ उत्तरी अक्षांशों तथा देशान्तरीय विस्तार 74̊ 44′ पूर्वी देशान्तर से 75̊ 25 ′ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। जिले की उत्तर से दक्षिण की लम्बाई लगभग 96 किमी॰ तथा पूर्व से किमी॰ तथा पूर्व से पश्चिम चोड़ाई 74 किमी॰ है। सीकर की उत्तरी सीमा झुन्झुनूँ जिले व हरियाणा राज्य से पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी सीमा जयपुर जिले से, दक्षिणी–पश्चिमी सीमा नागौर जिले से तथा उत्तरी–पश्चिमी सीमा चुरु से लगती है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 6 उपखण्डों, 6 तहसीलों) 8 नगरपालिकाओं तथा 8 पंचायत समितियो में विभक्त किया गया है।

मानचित्र 1:– अध्ययन क्षेत्र का मानचित्र

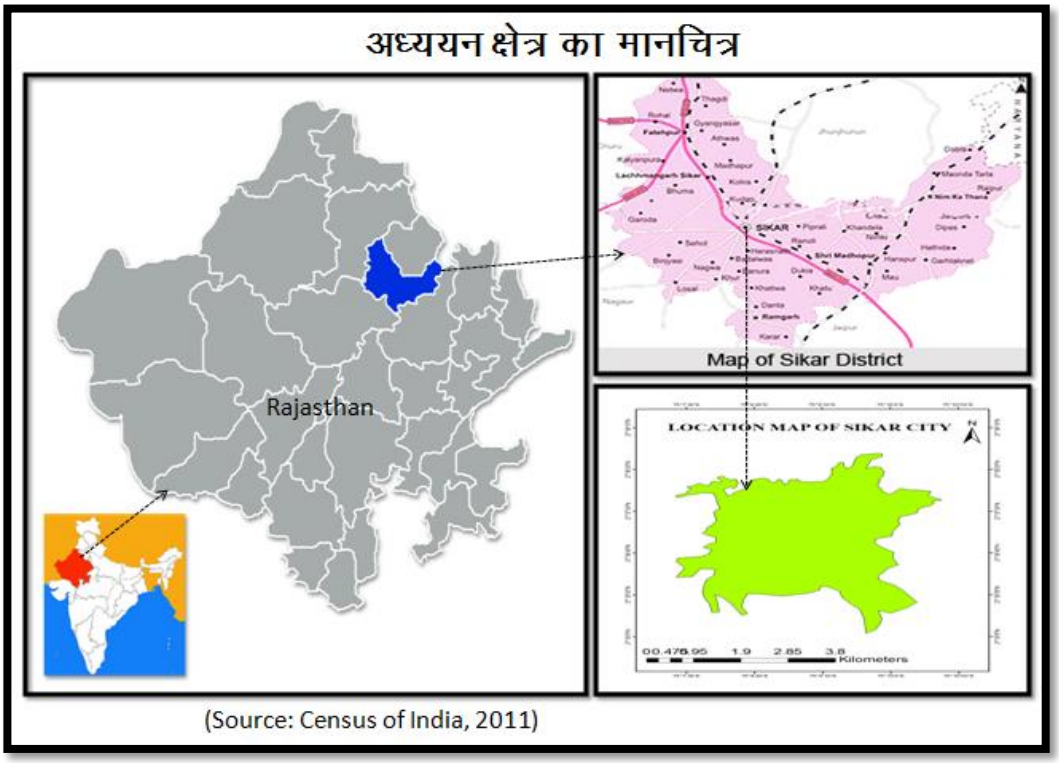

परिणाम

भारत एक विकासशील देश है यहां अन्य विकसित देशों की तुलना में नगरीकरण की गति मंद रही है। इस बात का अंदाजा इस आधार पर लगाया जा सकता है कि 1911 में यहां कुल नगरीय जनसंख्या मात्र 11 प्रतिशत थी, जो 1941 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 30 वर्ष में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि मात्र 3 प्रतिशत रही। 1951–61 के बीच नगरीय जनसंख्या में मात्र 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 1961 में नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.81 प्रतिशत रही व 2011 में नगरीय जनसंख्या 31.16 प्रतिशत रही। नगरीय जनसंख्या राजस्थान में देखें तो 1951 में 18.50 प्रतिशत थी व 1971 में 17.63 प्रतिशत रही वही 1991 में 22.88 प्रतिशत रही 2001 में 23.39 प्रतिशत व 2011 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 24.89 प्रतिशत रही। सीकर जिले में नगरीकरण की प्रवत्ति का वर्णन इस प्रकार है।

सारणी 1:– सीकर शहर में नगरीकरण की प्रवृत्ति का अध्ययन

वर्ष	नगरीय जनसंख्या	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
1921	21,080	–
1951	44,140	–
1981	1,02,970	43.99
1991	1,48,272	25.39
2001	1,85,925	31.50
2011	244,497	29.24

स्त्रोतः– सीकर नगर नियोजन विभाग

आरेख 1:– सीकर शहर में नगरीकरण की प्रवृत्ति का अध्ययन

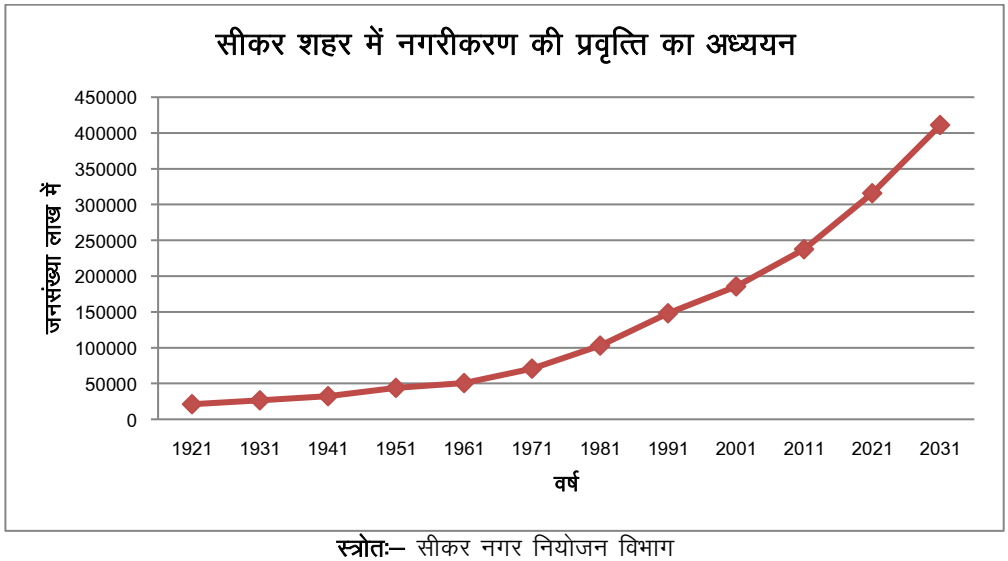

स्त्रोतः– सीकर नगर नियोजन विभाग

निम्न वृद्धि काल (1991 से पहले)

सामान्यतः नगरीकरण जनसंख्या मूल रूप से दो तरीकों से होती है, एक शहरी आबादी में वृद्धि के माध्यम से होती है, जो पूर्णतः प्राकृतिक वृद्धि होती है। दूसरा प्रवासन के माध्यम से होती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण से शहरी इलाकों में लोग प्रवास करते हैं। 1990 के दशक में जब भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, तो देश में तेजी से आर्थिक विकास में वृद्धि देखी गई। लेकिन यह आर्थिक विकास शहरी विकास से अधिक था, जिससे शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी का तेजी से प्रवास हुआ। वर्ष 1951 में केवल पांच शहरों में एक मिलियन से अधिक आबादी है, जो 2011 में 53 शहरों में बढ़ी है। सीकर शहर में शुरूआती दौर में नगरीकरण धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप देखा जा सकता है। सीकर शहर में नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करें तो स्पष्ट है कि इस समयकाल में 1921 में 21,080 नगर में रहती थी। जो 1951 में बढकर 44,140 एवं 1981 में 102,970 हो गई।

मध्यम वृद्धि काल (1991–2001 तक)

इस समयकाल में नगरीकरण में वृद्धि का कारण बेहतर शिक्षा सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि, अत्यधिक प्रवासित आबादी आधुनिकीकरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में बढोतरी थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा आर्थिक विकास का उद्देश्य एक और महत्वपूर्ण कारक था। इस अवधि में सीकर राजस्थान का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया है। कला, विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा प्रदान करने वाले कई सरकारी कॉलेजों के साथ–साथ कई निजी शैक्षणिक संस्थान भी खुल गए हैं। यही कारण है कि सीकर शहर में नगरीय जनसंख्या 1991 में 148,272 थी जो 2001 में बढकर 185,925 हो गई। जिसे यहां प्रस्तुत मानचित्र संख्या 2 में दिखाया गया है।

मानचित्र 2:– सीकर शहर में नगरीकरण की प्रवृत्ति का अध्ययन, 1991

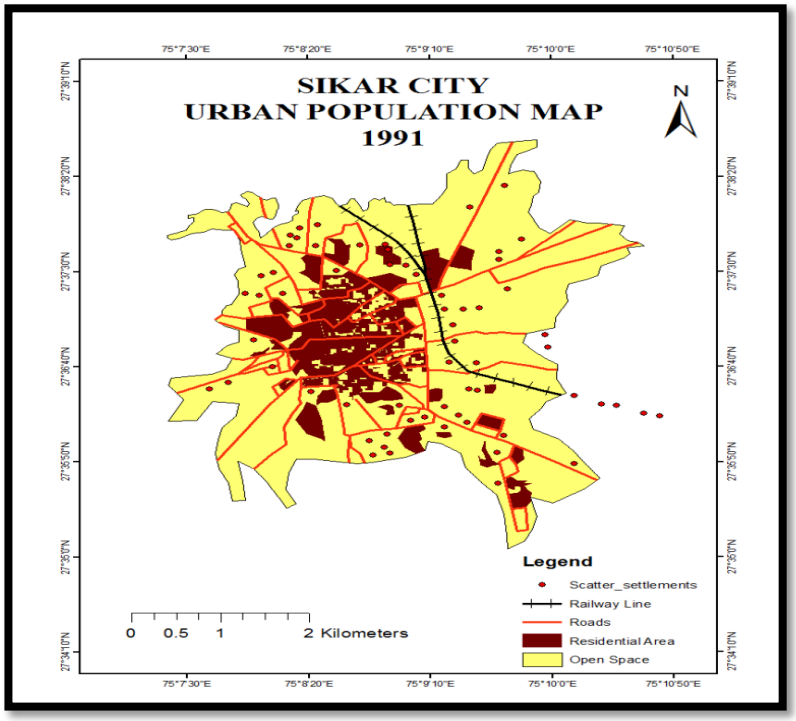

स्त्रोत :– https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/urbangrowth/urbangrowth.php

उच्च वृद्धि काल (2001–2020 तक)

इस समयकाल में नगरीकरण की वृद्धि हेतु प्रमुख कारकों में शहरी आकर्षण कारकों, कृषि की कम उत्पादकता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक प्रवासन देखा गया। इसके अलावा अस्पतालों की संख्या में वृद्धि एवं उच्च रोगी बिस्तरों की उपलब्धता इस बात का द्योतक है कि बढती स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहां नगरीकरण का एक प्रमुख कारण रही। इसके अलावा उद्योगों के विस्तार एवं उच्च रोजगार दशाओं के कारण सीकर शहर में नगरीकरण को प्रोत्साहन देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आधार पर स्पष्ट है कि सीकर शहर में नगरीय जनसंख्या 2001 में 185,925 थी जो 2011 में बढकर 244,497 हो गई। इस समयकाल में हुई नगरीय वृद्धि के कारण शहर में मलिन बस्तियों तथा अनेक पर्यावरणीय समस्याओं की उत्पति हुई है। जो भविष्य में अनेक नगरीय समस्याओं हेतु उत्तरदायी है।

मानचित्र 3:– सीकर शहर में नगरीकरण की प्रवृत्ति का अध्ययन, 2020

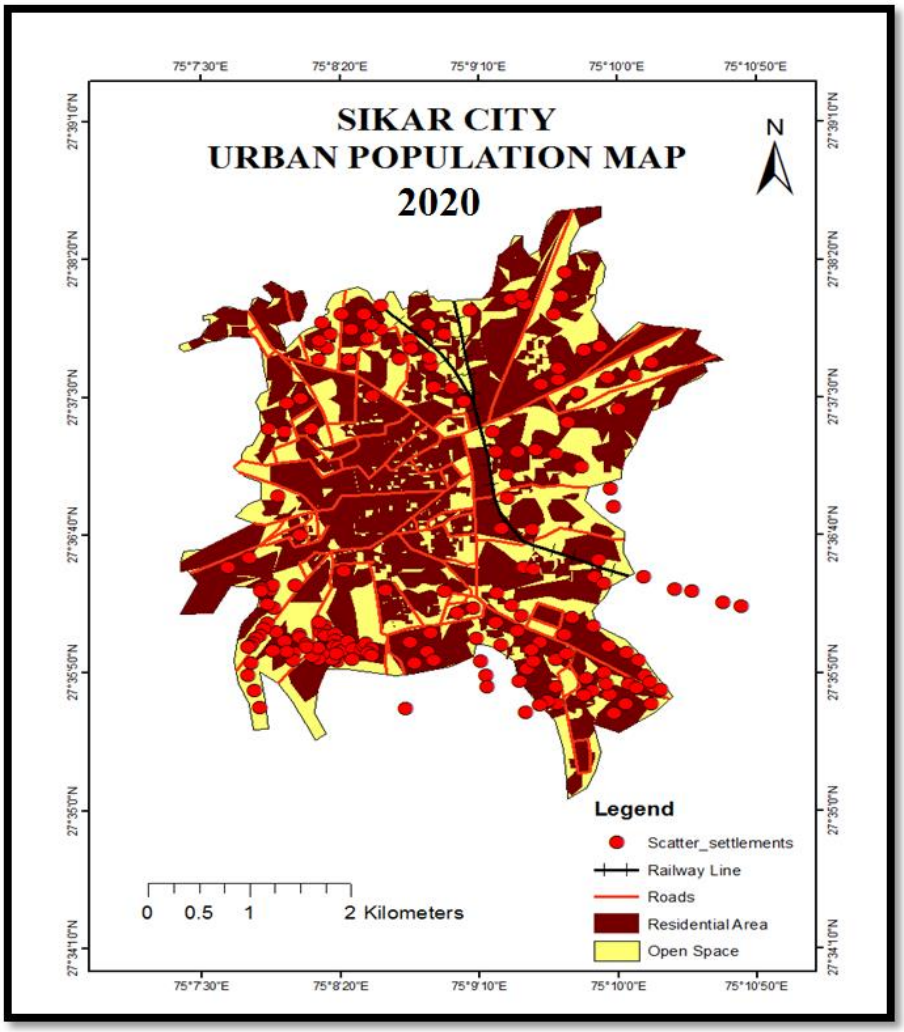

स्त्रोत :– https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/urbangrowth/urbangrowth.php

सीकर शहर में नगरीकरण का प्रभाव

लगातार बढ रहे नगरीकरण के कारण एक ओर जहां रोजगार साधनों में बढोतरी हुई है वहीं यह अनेक नगरीय समस्याओं हेतु भी उत्तरदायी है। नगरीकरण के कारण उत्पन्न सकारात्मक प्रभावों में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों का प्रवासन ,शहरी केंद्रों में रोजगार के अवसर, परिवहन और संचार सुविधाएं, शिक्षण सुविधाएं, जीवन स्तर में वृद्धि एवं लोगों को उच्च रहने–सहने की दशाएं प्रदान की हैं वहीं शहर के विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी पडे हैं। नगरीकरण में तेजी और अप्रयुक्त शहरी विकास के कारण काफी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप आवासीय समस्याएं, जल और स्वच्छता समस्या, आधारभूत सुविधाओं का अभाव तथा मलिन बस्तियों की समस्या एक प्रमुख समस्या के तौर पर उभर कर सामने आई है। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के कारण एवं बढते पर्यावरण प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोगों में भी बढोतरी दर्ज की गई है जो किसी भी क्षेत्र के विकास में बाधक हो सकती है। भारत में वास्तविक शहरों का विकास दो प्रमुख मुद्दों से बाधित है। सबसे पहले, ग्रामीण इलाकों में शहरी उपयोग के लिए कुल भूमि क्षेत्र कम है, दूसरा आवासीय उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए दी गई शहरी भूमि का आवंटन अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक कम है। आर्थिक विकास शहरीकरण के साथ सहसंबंधित है। इसका तात्पर्य है कि शहरी उपयोग के लिए भूमि उपलब्धता को आर्थिक विकास के साथ तालमेल रखने की जरूरत है।यह सत्य है कि शहरी कार्यों के लिए भूमि उपयोग में वृद्धि हुई है परंतु अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के मुताबिक विकास धीमा रहा है। यह दो रूपों में परिलक्षित होता है। सबसे पहले, ग्रामीण की तुलना में शहरी क्षेत्र में जमीन की कीमत बहुत अधिक है। दूसरा, निर्माण की लागत की तुलना में भूमि की कीमत बहुत अधिक है। ये विशेषताएं कई अन्य विकासशील देशों के प्रमाण भी हो सकती

हैं। संबंधित कारणों से, शहर में भारी वृद्धि देखी गई है जिसके लिए आगे सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता है।

सुझाव

नगरीकरण के कारण उपयुक्त समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा सूक्ष्म स्तर पर नगरीकरण हेतु उपयुक्त नियोजन को महत्व दिया जाए, साथ ही भूमि नियोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिएं ताकि नगरीय समस्याओं का उचित समाधान किया जा सके। शहर में आधारभूत सरंचना एवं शहरी सुविधाओं में बढ़ोतरी हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाये जाने चाहिएं। शहर को विकास के पथ पर गतिमान बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि एक सुस्पष्ट नगरीकरण नीति एवं क्षेत्रीय योजना का निर्माण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, ताकि बढ़ती बेरोजगारी कि समस्या को दूर किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत विकासशील अर्थव्यवस्था में से एक है शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना सुविधा विकसित करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है और वित्त पोषण, शासन, योजना और नीति बनाने वाले क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। शहरीकरण को देश के आर्थिक विकास की आवश्यकता है, लेकिन शहरीकरण का कृषि उत्पादन और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बढ़ते शहरीकरण से कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य में प्रयोग किया जाने लगा है इससे कृषि भूमि में कमी आई है। महायोजना के अध्ययन से स्पष्ट है कि यहाँ भविष्य में नगरीकरण में और भी अधिक वृद्धि संभव है। लगातार बढ़ती स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं बढ़ते आधुनिकीकरण से यहाँ नगरीय विकास को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है।

संदर्भ सूची

1. Agrawal, S.N. (2003) India's Population Problem. International Journal of Multidisciplinary Education and Research ISSN: 2455-4588. Volume 2. Issue 4. Page No. 48-50.
2. Annual Report. (2010-2011) Career Point Infosystems Limited.
3. Beker & Ven Duran. (2009) Land use and Land Cover Change in Developing Countries,pp 47-60.
4. Bhagawat, Rimal. (2011) Journal of Theoretical and Applied Information Technology. ISSN: 2325-2089. Volume-3, Issue-15.
5. Bose, Ashish. (1982) India's Urbanization, International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR) ISSN: 2321-0869 (O) 2454-4698 (P), Volume-3, Issue-8.
6. Haryana district gazetteers (1995) Bhiwani, Haryana gazetteers organisation, revenue departments, Chandigarh (India).
7. Jain, N.G. (1990) Level of Regional Urbanization and Development. Urbanization and Regional Development. Imperial Journal of Interdisciplinary Research .Vol-3, Issue-1.
8. Lambian. (2009) Changing Land use Pattern in India, International Journal of Computing and Corporate Research, Volume 2 Issue 6 November, pp 69-84.
9. Longley. Et al." On the measurement and generalization of urban form." Environment and Planning a 32, no. 3 473-488.
10. Mamoria, C.B. (1986) India's Population Problem, The Urban World, Mc Graw Hill Book Co., 3, 121, P,7.
11. Mandal, R.B. (2000) Urban Geography: A textbook,Concept Publishing Co.
12. Singh, Mahima. (2014) 'Land Use Changes in developing countries – A Spatio – Temporal Study'. Institute of Town Planners, India Journal, pp 96-106.
13. Singh, J.P. (1993), Urbanization and Regional Development in Haryana 1951-1981. International Journal of Humanities and Social Science Invention. www.ijhssi.org Volume 4 .Issue 5. PP.11-20.
14. Singh, manprit etal. (2018) Land use/land cover change detection analysis using remote sensing and GIS of Dhanbad district, India. Eurasian Journal of Forest Science. 6(2). 1-12.
15. Yadav, K.N.S. (2010) Migration Urbanization and Economic Development, Migration Studies. International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication, ISSN: 2320-2084 Volume-4, Issue-12.